(ख) और (ग). सरकार ग्राम विकास को उच्चतम प्राथमिकता दे रही है । पिछले वर्ष में विभिन्न ग्राम विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए सुलभ कराए गए लगभग 94 करोड़ रुपए के मुकाबले में वर्तमान बजट में 168 करोड़ रुपए की धनराशि सुलभ हो गई है । विशिष्ट रूप से, लघु तथा सीमान्त किसान विकास एजेंसियां, सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम आदिवासी क्षेत्र तथा पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम जैसे कुछेक महत्वपूर्ण कार्यक्रमों के लिए पिछले वर्ष के लगभग 64 करोड़ रुपए के मुकाबले में इस वर्ष 99 करोड़ रुपए की धनराशि सुलभ की गई है ।

समन्वित ग्राम विकास का एक कार्यक्रम गत वर्ष आरम्भ किया गया तथा इसके लिए 20 जिले चुने गए थे । इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम, जिसका मुख्य उद्देश्य 'गरीब ग्रामीण' तथा 'लाभहीन वर्गों' के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना है, जो नयी दिशा दी गई है ताकि यह एक निश्चित समय में गरीब ग्रामीणों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए वास्तव में साधन बन सके । वर्तमान सरकार विद्यमान 20 जिलों के अलावा और अधिक क्षेत्र में विभिन्न ग्राम विकास योजनाओं की पहुंच तथा पद्धति में एकता लाने के बारे में भी विचार कर रही है ।

सरकार बेरोजगारी तथा अल्प-रोजगार की समस्याओं से भी चिंतित है और बजट प्रस्ताव तैयार करते समय इस विशेष पहलू को ध्यान में रखा गया था । चालू कार्यक्रमों के अलावा, इस वर्ष ग्रामीण इलाकों में सम्पर्क सड़कें, ग्रामीण बजारों का विकास तथा रेगिस्तान विकास जैसी तीन नई योजनायें शुरु की जा रही हैं जिससे कि ग्रामीण आधारभूत ढांचे को मजबूत बनाया जा सकें और आर्थिक तथा सामाजिक असुविधाओं से पीड़ित क्षेत्र में विकास की गति में तेजी लाई जा सके । ग्रामीण इलाकों में अतिरिक्त रोजगार पैदा करने हेतु फालतू स्टाक से खाद्यान्नों का उपभोग करने की भी एक योजना आरम्भ की गई है । इस तरह, चल रहे विभिन्न ग्राम विकास कार्यक्रमों तथा शुरु की जा रही नई योजनाओं का मुख्य बल समग्र ग्राम विकास करने तथा ग्रामीण इलाकों में विशेषकर 'गरीब ग्रामीणों' तथा अन्य 'लाभहीन वर्गों' के लिए अतिरिक्त रोजगार के अवसर पैदा करने पर हैं ।

विकलांगों को ऋण सम्बन्धी सुविधाएं

5511. **श्री एस० एस० सोमानी** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विकलांगों को ऋण सुविधायें प्रदान करने के लिए कोई योजना आरम्भ की है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उक्त योजना के अन्तर्गत किस प्रकार की संस्थायें सम्मिलित की गई हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) भारत सरकार (वित्त मंत्रालय) ने विकलांग व्यक्तियों को लाभकर व्यवसाय चलाने के लिए तथा विकलांग व्यक्तियों से संबंधित संस्थाओं को लाभकर व्यवसाय चलाने हेतु टिकाऊ उपकरणों तथा/या कच्चा माल खरीदने के लिए अन्य बातों के साथ-साथ कर्ज देने के लिए "डिफेंशियल रेट आफ इन्ट्रेस्ट स्कीम" नामक एक योजना तैयार की है । ये कर्जे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों तथा प्रमुख उत्तरदायी अराष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दिये जायेंगे ।

(ख) और (ग) . वित्त मंत्रालय द्वारा "डिफेंशियल रेट आफ इन्ट्रेस्ट स्कीम" के सम्बन्ध में जारी की गई मार्गदर्शक बातों

की एक-एक प्रति अतारांकित प्रश्न संख्या 910, 957 तथा 842 के उत्तर में 17 जून, 1977 को सभा के पटल पर रख दी गई थी।

बिहार के लिए सिंचाई योजनाएं

5512. **श्री मृत्युंजय प्रसाद वर्मा** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार राज्य की सिंचाई सम्बन्धी कितनी और कौन कौन सी योजनाएं केन्द्रीय सरकार के स्वीकृति के लिये विचराधीन हैं ;

(ख) उन स्वीकृति सिंचाई योजनाओं की संख्या तथा नाम क्या हैं जिनके लिये मांगी गई संपूर्ण धन राशि आवंटित की गई है और प्रत्येक स्वीकृत सिंचाई योजना के लिय कितनी कितनी धनराशि आवंटित की गई ;

(ग) कितनी और किन किन स्वीकृत योजनाओं के लिये कितना आंशिक धनराशि आवंटित की गई; और

(घ) आवंटित धन राशि के उपयोग, समपयोग और दुरुपयोग के सम्बन्ध में अद्यतन ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) बिहार की 16 वृहद् और 30 मध्यम नई सिंचाई स्कीमों पर इस समय केन्द्रीय जल आयोग में विभिन्न चरणों में तकनीकी समीक्षा की जा रही है; यह तकनीकी समीक्षा राज्य सरकार के साथ परामर्श करते हुए की जा रही है। इन स्कीमों की सूची उपाबंध एक में दी गई है। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल टी– 879/77]**

(ख) और (ग) इन स्कीमों का ब्यौरा उपाबंध-दो में दिए गए विवरण में दिया गया है।

(घ) 1976–77 के लिए वृहद और मध्यम सिंचाई स्कीमों के लिए 51.00 करोड़ रुपये परिव्यय अनुमोदित किया गया था और यह राशि उस वर्ष पूर्ण रूप से खर्च कर ली गई थी। 1977–78 में 71.61 करोड़ का अनुमोदित परिव्यय रखा गया है जिसके पूरी तरह से उपयोग कर लिए जाने की संभावना है

Soil Survey in Major Projects

5513. SHRI P. RAJAGOPAL NAIDU: Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state:

(a) whether soil survey was done in the Ayacut of Nagarjunasagar and other major projects in the country; and

(b) if not, whether that survey is to be conducted?

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI SURJIT SINGH BARNALA): (a) Soil Survey has already been done in Nagarjunasagar Project. Since these surveys were not being carried out by the States in respect of irrigation projects earlier, Planning Commission have issued in March 1974 a directive to the State Governments that major Irrigation Project Reports to be submitted to Central Water Commission from 1st March, 1975 onwards should include report on soil surveys of the Command Areas.

(b) Does not arise.

Allotment of Shop Plots in Lawrence Road, New Delhi

5514. SHRI KANWAR LAL GUPTA: Will the Minister of WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Delhi Development Authority gave an advertisement in 'The Statesman' dated 6th July, 1977 for the allotment of shop plots in Lawrence Road, New Delhi;

(b) is it also a fact that the size of the plot is 13.5 sq. mt. and the price for corner and non-corner plot is Rs. 12,900|-and 9,000|-respectively;